भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4429

जिसका उत्तर 30 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

09 चैत्र, 1944 (शक)

डाटा केंद्र तथा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

4429. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री रवि किशन:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री मनोज तिवारी:
श्री रंग आप्पा बारणे:
श्री बिद्युत बरन महतों:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री प्रतापराव जाधव:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत की डिजिटल गति में तेजी लाने के लिए अपना डाटा केंद्र क्षेत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में ऐसे डाटा केंद्र की स्थापना से होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या सरकार एक नई राष्ट्रीय डाटा केंद्र नीति तैयार करने पर भी विचार कर रही है और यदि हां, तो उक्त नीति की मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ड) क्या सरकार ने इस संबंध में हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है और यदि हां, तो हितधारकों की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा भारत को वैश्विक डाटा केंद्र हब बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) : जी,हां ।

(ख) : यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) : इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार ने डिजिटल अभिगम , डिजिटल समावेश , डिजिटल सशक्तिकरण और डिजिटल विभाजन को पाटना सुनिश्चित करके भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान -आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से ' डिजिटल इंडिया ' कार्यक्रम शुरू किया। संक्षेप में , हमारा मिशन यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुधार करें ; भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करें , देश में रोजगार और वैश्विक डिजिटल तकनीकी क्षमताओं का सृजन करें ।

देश भर में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एमईआईटीवाई द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों की स्थिति अनुबंध में दी गई है।

(घ) : हां, डेटा केंद्र और क्लाउड समग्र डिजिटल इंडिया अवसंरचना पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग हैं।

(ङ.) : हां, मंत्रालय सभी नीतियों के लिए एक मानक के रूप में सार्वजनिक परामर्श आयोजित करता है। 25 फरवरी 2022 को चेन्नई में हाल ही में सार्वजनिक परामर्श जिसमें 65 से अधिक कॉर्पोरेट और केंद्र / राज्य सरकार के अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से और 295 से अधिक अन्य हितधारकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया था। प्राप्त इनपुट का अध्ययन किया जा रहा है।

(च) : सरकार के पास अपना एक स्पष्ट उद्देश्य है कि भारत देश ने डेटा केंद्र और क्लाउड हब के रूप में स्थान बनाया है।

****

अनुबंध

देश भर में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एमईआईटीवाई द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है::

• **आधार:** आधार 12 अंकों की बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी आधारित पहचान प्रदान करता है जो अद्वितीय, आजीवन, ऑनलाइन और प्रामाणिक है। इसके अलावा आधार को वैधानिक समर्थन देने के लिए 'आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016' को 26 मार्च 2016 को अधिसूचित किया गया था। 132 + करोड़ से अधिक निवासियों को नामांकित किया गया है।

• **सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी):** सामान्य सेवा केंद्र परियोजना का लक्ष्य देश भर में 2.50 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) में कम से कम एक सीएससी स्थापित करना है, ताकि विभिन्न सरकार को नागरिक (जी2सी) और अन्य नागरिक केंद्रित ई- सेवाओं की प्रदायगी की जा सके। यह एक आत्मनिर्भर उद्यमिता मॉडल है जो ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) द्वारा चलाया जाता है । फरवरी, 2022 तक कुल 4.63 लाख सीएससी क्रियाशील (शहरी + ग्रामीण) हैं, जिनमें से 3.63 लाख सीएससी जीपी स्तर पर कार्य कर रहे हैं ।

• **डिजिटल लॉकर:** डिजिटल लॉकर जारीकर्ताओं के लिए डिजिटल रिपॉजिटरी में दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए रिपॉजिटरी और गेटवे के संग्रह के साथ एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है। डिजिलॉकर के अब तक 9.23 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर हो चुके हैं। 486 करोड़ प्रामाणिक दस्तावेज जारी किए गए हैं। 1695 जारीकर्ता और 349 अनुरोधकर्ता संगठनों को शामिल किया गया है।

• **नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग):** प्रमुख सरकारी सेवाओं को वितरित करने के लिए उमंग को एकल मोबाइल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। वर्तमान में, भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) उपयोगिता सेवाओं की 20,527 सेवाओं के साथ-साथ 279 केंद्र/राज्य सरकार के विभागों/33 राज्यों की एजेंसियों की 1,417 सेवाओं को उमंग पर शामिल किया गया है।

• **ई-हस्ताक्षर:** ई-हस्ताक्षर सेवा नागरिकों द्वारा कानूनी रूप से स्वीकार्य रूप में ऑनलाइन फॉर्म/दस्तावेजों पर तत्काल हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करती है। यूआईडीएआई की ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग करते हुए विभिन्न अनुप्रयोगों द्वारा सेवाओं का लाभ उठाया जा रहा है। जारी किए गए कुल ई- हस्ताक्षर 23.72 करोड़ हैं और सी-डैक द्वारा जारी किए गए 4.45 करोड़ से अधिक ई-हस्ताक्षर हैं।

• **माईगव**: माईगव भारत में सहभागी शासन के लिए अपनी तरह का पहला नागरिक जुड़ाव मंच है। माईगव का उद्देश्य नागरिकों और सरकार के बीच संवाद को सुगम बनाना, नागरिकों को सरकार के करीब लाना और सरकार को इस मंच के माध्यम से नागरिकों के करीब लाना है। वर्तमान में, 2.25+ करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता माईगव के साथ पंजीकृत हैं, माईगव प्लेटफॉर्म पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।

• **डिजिटल गांव:** एमईआईटीवाई ने अक्टूबर, 2018 में 'डिजिटल गांव प्रायोगिक परियोजना भी शुरू की है। इस परियोजना के तहत 700 ग्राम पंचायतों (जीपी)/कम से कम एक ग्राम पंचायत/गांव प्रति जिला प्रति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ शामिल किया जा रहा है । डिजिटल सेवाओं डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवा, वित्तीय सेवाएं, कौशल विकास, सौर पैनल संचालित स्ट्रीट लाइट, जैसे पेशकश की जा रही है जिसमें सरकार से नागरिक सेवाएं (जी2सी), बिजनेस टू सिटिजन (बी2सी) सेवाएं शामिल हैं।

• **ई-जिला एमएमपी का राष्ट्रीय रोलआउट:** ई-जिला एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) है जिसका उद्देश्य जिला या उप-जिला स्तर पर पहचान की गई उच्च मात्रा में नागरिक केंद्रित सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक प्रदायगी करना है। 28 राज्यों/ 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 709 जिलों में कुल 3,916 ई-जिला सेवाएं शुरू की गई हैं।

• **ओपन सरकार डेटा प्लेटफ़ॉर्म:** ओपन गवर्नमेंट डेटा (ओजीडी) प्लेटफ़ॉर्म भारत सरकार की ओपन डेटा पहल का समर्थन करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म है। यह सरकार के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने का इरादा रखता है और अलग-अलग परिप्रेक्ष्य देने के लिए सरकारी डेटा के कई और नवीन उपयोगों के रास्ते भी खोलता है। वर्तमान में, ओजीडी प्लेटफॉर्म में 243 विभागों के 428 सीडीओ के साथ 5,26,805 संसाधन हैं, 12,064 कैटलॉग, 2,599 विज़ुअलाइज़ेशन और 1,29,396 एपीआई विकसित किए गए हैं।

• **ई-अस्पताल/ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस):** ई-अस्पताल आवेदन अस्पतालों के आंतरिक कार्यप्रवाह और प्रक्रियाओं के लिए अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है। ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस) के साथ-साथ ई-अस्पताल अनुप्रयोगों को एनआईसी के राष्ट्रीय क्लाउड पर होस्ट किया जाता है। वर्तमान में, 23.38 करोड़ से अधिक ई-अस्पताल लेनदेन के साथ 631 अस्पतालों को ई-अस्पताल पर जोड़ा गया है, और ओआरएस से 49 लाख से अधिक नियुक्तियों के साथ देश भर के 422 अस्पतालों द्वारा ओआरएस को अपनाया गया है।

• **जीवन प्रमाण:** जीवन प्रमाण के रूप में जानी जाने वाली पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र योजना में जीवन प्रमाण पत्र हासिल करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की परिकल्पना की गई है। इस पहल के साथ, पेंशनभोगी को संवितरण एजेंसी या प्रमाणन प्राधिकरण के सामने खुद को शारीरिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । 2014 से अब तक 557.63 लाख से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र संसाधित किए जा चुके हैं।

• **एनसीओजी-जीआईएस अनुप्रयोग:** राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान केंद्र (एनसीओजी) परियोजना, विभागों के लिए साझाकरण, सहयोग, स्थान आधारित विश्लेषण और निर्णय समर्थन प्रणाली के लिए विकसित एक जीआईएस मंच है। अब तक विभिन्न क्षेत्रों में 605 आवेदन कार्य कर रहे हैं।

• **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क:** एनकेएन का उद्देश्य देश भर में सभी ज्ञान संस्थानों को उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना है ताकि संसाधनों और सहयोगी अनुसंधान को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को आपस में जोड़ने के लिए एक उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क स्थापित किया गया है । 28 फरवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार एनकेएन के तहत 1700 से अधिक संस्थानों को कुल 1756 लिंक प्रदान किए गए हैं ।

• **ई-अवसंरचना :** डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में, एमईआईटीवाई ने पांच विश्वविद्यालयों में वाई-फाई सक्षम कैंपस नेटवर्क की स्थापना को सफलतापूर्वक लागू किया है: इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, उत्कल विश्वविद्यालय और नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी (एनईएचयू)

• **प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा):** सरकार ने 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को शामिल करके ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता की शुरुआत करने के लिए "प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)" नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है । 24 मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार कुल लगभग 5.77 करोड़ उम्मीदवारों और 4.87 करोड़ को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 3.60 करोड़ उम्मीदवारों को पीएमजीदिशा योजना के तहत प्रमाणित किया गया है। यह योजना देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है।

• **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई):** यूपीआई एक अग्रणी डिजिटल भुगतान मंच है। यह एक ही मोबाइल एप्लिकेशन (भाग लेने वाले किसी भी बैंक हेतु) में कई बैंक खातों को शक्ति प्रदान करता है, कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान को एक हुड में मिलाता है। यह "पीयर टू पीयर" संग्रह अनुरोध को भी पूरा करता है जिसे शेड्यूल किया जा सकता है और आवश्यकता और सुविधा के अनुसार भुगतान किया जा सकता है। 229 बैंक यूपीआई सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

• **फ्यूचर स्कील प्राईम:** एमईआईटीवाई ने नेसकॉम के सहयोग से फ्यूचर स्कील प्राईम नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में आईटी पेशेवरों का पुन: कौशल/उन्नयन करना-कौशल है जिसमें ऑगमेंटेड/वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग/ 3डी प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सामाजिक और मोबाइल, साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन शामिल हैं।

• **साइबर सुरक्षा:** साइबर कानून, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (2000 का 21) (आईटी अधिनियम के प्रशासन से संबंधित मामले। और अन्य आईटी संबंधित कानून "एमईआईटीवाई के दायरे में आते हैं। मूल आईटी अधिनियम, 2000 को प्रशासित करते समय, एमईआईटीवाई के पास बेहतर इंटरनेट शासन, डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा इंटरनेट पर गोपनीयता, प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रचार-प्रसार और विनियमन और ई-शासन के संविधान को सुनिश्चित करने की विशिष्ट जिम्मेदारी है । भारत ने 29 जून, 2021 को प्रमुख साइबर सुरक्षा मानकों पर दुनिया के दसवें सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में रैंक करने के लिए 37 स्थान से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा शुरू किए गए वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (जीसीआई) 2020 में शीर्ष 10 में जगह बनाई है।

• **बीपीओ प्रोत्साहन योजना:** भारत बीपीओ प्रोत्साहन योजना (आईबीपीएस) और उत्तर पूर्वोतर बीपीओ प्रोत्साहन योजना (एनईबीपीएस) देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश और पूर्वोतर क्षेत्र के छोटे शहरों में बीपीओ/आईटीईएस संचालन स्थापित करके शुरू की गई थी। । बीपीओ प्रोत्साहन योजनाओं का उद्देश्य देश भर में बीपीओ/आईटीईएस संचालन के संबंध में कुल 53,300 सीटों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। कुल मिलाकर, इन योजनाओं के तहत बीपीओ/आईटीईएस संचालन की स्थापना के लिए पात्र संस्थाओं को 61,208 सीटें आवंटित की गईं।

• **इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण**

o संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज (एम-सिप्स): वर्तमान की स्थित अनुसार, लगभग 83,958 करोड़ रूपए के प्रस्तावित निवेश के साथ 308 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।

o इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी): 1538 करोड़ रूपए की सरकारी सहायत अनुदान सहित 3,762 करोड़ रूपए परियोजना लागत के साथ 3,464 एकड़ क्षेत्र में 19 ग्रीनफील्ड और सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) देश भर के 15 राज्यों में मंजूर किए गए है। ईएमसी योजना के तहत आवेदनों की प्राप्ति समाप्त होने के आधार पर, एमईआईटीवाई ने देश में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए बुनियादी ढांचे के आधार को और सुदृढ़ करने और इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के लिए 1 अप्रैल, 2020 को संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना अधिसूचित की। अब तक, 681.04 करोड़ रू. की केंद्रीय वित्तीय सहायता सहित 1,410 करोड़ रू. की परियोजना लागत से 1,040 एकड़ क्षेत्र में ईएमसी की स्थापना के लिए दो आवेदनों की मंजूरी दी गई है।

****